Veer Arjun

ndian medical association suru karegi Save The Doctor andolan

Date: 31/07/2013 | Edition: Delhi | Page: 4 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 26 H: 12

Clip: 1 of 1

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शुरू करेगी सेव द डॉक्टर आंदोलन

हमारे संवाददाता

नई दिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) तथा एसोसिएशन आफ हैल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) ने आज यहां देशभर से चिकित्सा छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर देशव्यापी जन आंदोलन 'सेव द डाक्टर' शुरू करने की घोषणा की है जिसके तहत अंडर ग्रेजुएशन (यूजी) और पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) मेडिकल सीटों की संख्या बराबर करने की मांग की जा रही है। यह देशव्यापी जन आंदोलन नीति-निर्माताओं और देशभर में सक्रिय चिकित्सा संस्थानों को प्रभावित करने के मकसद से शुरू किया गया है। मेडिकल छात्रों की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती को इंटर्नशिप और पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए। देशभर में करीब दो से तीन लाख मेडिकल छात्रों द्वारा इस अभियान को समर्थन दिए जाने की संभावना है। किसी भी डाक्टर के लिए विशेषज्ञ बनने के मकसद से चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है जिसे पूरा कर वे गाइनोकोलाजिस्ट, न्यूरोलाजिस्ट, सर्जन, रेडियोलाजिस्ट आदि बन सकते हैं। देश के चिकित्सा संस्थानों में पीजी की कम सीटों के चलते आज भारत में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी है। हालांकि भारत में सबसे अधिक संख्या में चिकित्सा संस्थान हैं लेकिन पीजी और यूजी छात्रों के लिए आबंटित सीटों में गैर-बराबरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य पोस्टिंग जैसी शर्तों के चलते युवा डाक्टर काफी प्रभावित होते हैं वे 13 साल का लंबा कार्यकाल सिर्फ पढ़ाई करने पर ही लगाने को मजबूर हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली भविष्य में भी इसी प्रकार जोखिम से घिरी रहेगी और आने वाले समय में वरिष्ठ विशेषज्ञ

–डाक्टरों के लिए गांवों में जाना अनिवार्य करना होगा : सैनी

डाक्टरों/सर्जनों के सेवानिवृत्त होने के बाद देश में विशेषज्ञ डाक्टरों की और भी कमी होगी।

डॉ. नरेंद्र सैनी, महासचिव, आईएमए ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती का समर्थन करता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसे अनिवार्य किया जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित तैनाती की कोई प्रणाली नहीं है। प्रत्येक पीजी छात्र को अपने कोर्स/इंटर्नशिप के दौरान छह माह तक ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती को अवश्य पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यकाल में कम से कम 4 से 5 पदोन्नतियों का अधिकारी होता है। हर प्रमोशन के बदले, एक साल की ग्रामीण पोस्टिंग को अनिवार्य बनाया जा सकता है।

वर्ल्ड हैल्थ स्टैटिस्टिक्स की जानकारी के अनुसार भारत में 1000 की आबादी पर 0.9 बिस्तर हैं जो 2.9 बिस्तरों के वैश्विक औसत से काफी कम है। भारत के स्वास्थ्यरक्षा तंत्र की बदहाली का एक नमूना उन लाखों गर्भवती युवतियों के रूप में दिखाई देता है जो प्रसव के दौरान जीवन से हाथ धो बैठती हैं। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि पीजी सीटों का अभाव देश में बहुमूल्य जिंदगियों के खिलवाड़ का कारण बन रहा है। देश में हर साल करीब 2.8 करोड़ शिशु जन्म लेते हैं यानि हर वर्ष 2.8 करोड़ प्रसवों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए देश को काफी बड़ी संख्या में महिला रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है लेकिन हमारे पास कुल 40 हजार गाइनोकोलाजिस्ट ही हैं और उनमें से ज्यादातर मुख्य रूप से शहरों में ही हैं। हमारी सरकार मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लाखों रुपये खर्च करती है लेकिन उसे इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। दरअसल नीति-निर्माता और अन्य लोग यह नहीं समझ पा रहे कि गर्भवती युवतियां पैसों के अभाव में दम नहीं तोड़ रहीं बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में पर्याप्त संख्या में गाइनोकोलाजिस्ट और नियोनेटोलाजिस्ट नहीं हैं जो जच्चा-बच्चा की देखभाल कर सकें।

डॉ. नवनीत मुतरेजा, समन्वयक, अभियान सेव द डाक्टर पर कहा कि यदि इन हालातों में बदलाव नहीं होता तो हमें काफी कड़े कदम उठाने होंगे जिनमें दूसरे देशों से सर्जनों का आयात शामिल है। हाल में जनता का दबाव बढ़ने में ब्राजील के प्रधानमंत्री ने क्यूबा से छह हजार विशेषज्ञ डाक्टरों के आयात को मंजूरी दी है।